

[2023] 3 एस. सी. आर 892

राणा अयूब

वी.

प्रवर्तन का निर्देश

इसके सहायक निदेशक के माध्यम से

(2023 की लिखित याचिका (अपराधिक) संख्या 12)

फरवरी 07,2023

[वी. रामसुब्रमणियन और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002। 3 , 4 , 44 और 45-दंड संहिता, 1860 एस. एस. 4.3 , 406 , 418 , 420 - जानकारी प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008-एस। 66 डी-काला धन अधिनियम। 4 - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999-एस। 37 - आमदनी

कर अधिनियम, 1961-एस. 133 (6) - महामारी के दौरान याचिकाकर्ता ने एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके क्राउडफंडिंग अभियान चलाया

" केटो "-प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय

फेमा के तहत जांच शुरू की गई-साथ ही, गाजियाबाद में एक व्यक्ति (निजी शिकायतकर्ता) द्वारा अपराधों के लिए एक शिकायत दर्ज की गई थी।

403 , 406 , 418 , 420 आई. पी. सी., एस. 66 डी. आई. टी. अधिनियम और एस. 4 काला धन अधिनियम-इस बीच ईडी का मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय

याचिकाकर्ता को कुछ दस्तावेजों से संबंधित जवाब मांगने के लिए नोटिस जारी किया गया और याचिकाकर्ता ने नोटिस का पालन किया-इसके बाद, ईडी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने गाजियाबाद में विशेष न्यायाधीश के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया कि निजी शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत-इसके बाद नवी मुंबई में स्थित याचिकाकर्ता के बैंक खाते को कुर्क करने का अस्थायी आदेश ईडी द्वारा पारित किया गया था-इसके बाद, विशेष न्यायाधीश, गाजियाबाद ने ईडी (प्रतिवादी) द्वारा दर्ज शिकायत का संज्ञान लिया और याचिकाकर्ता को पेश होने के लिए बुलाया-याचिकाकर्ता को समन करने के आदेश से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि विशेष न्यायाधीश गाजियाबाद का कथित अपराध पर कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है।

- आयोजित किया गया: अपराध की आय का अधिग्रहण आभासी दुनिया में हुआ है, जिन स्थानों से धन का ऑनलाइन हस्तांतरण हुआ है, केवल याचिकाकर्ता या उनके बैंकों को ही पता है-तत्काल मामले में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के सवाल के लिए तथ्य के सवाल की जांच की आवश्यकता होती है कि अपराध की कथित आय को (i) छिपाया गया था; या (ii) कब्जा कर लिया गया था; या (iii) अर्जित किया गया था; या (iv) उपयोग किया गया था-तथ्य का यह सवाल इस बात पर निर्भर करेगा कि

892 राणा अयूब बनाम। अपने सहायक निदेशक के माध्यम से प्रवर्तन का निर्देश

साक्ष्य जो विचारण न्यायालय के समक्ष सामने आता है-क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का निर्णय रिट याचिका में नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब स्थान/स्थानों के बारे में गंभीर तथ्यात्मक विवाद हो।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002। 44 - अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का अधिकार क्षेत्र-आयोजित: पी. एम. एल. ए. की धारा 44 और आई. डी. 1 की धारा 177 से 184 के प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (सी) के विशिष्ट अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, पी. एम. एल. ए. के तहत गठित विशेष न्यायालय को अनुसूचित अपराध पर भी मुकदमा चलाने का अधिकार होगा-भले ही अनुसूचित अपराध को किसी अन्य न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया हो। वह न्यायालय, संबंधित प्राधिकारी द्वारा एक आवेदन पर, उस विशेष न्यायालय को यह कार्य सौंपेगा जिसने धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया है।

रिट याचिका खारिज करते हुए, अदालत ने

पकड़ना: 1. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 44 (1) (ए) के तहत ऐसी स्थिति है जहां

कोई जटिलता नहीं है। धारा 44 (1) (ए) क्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित सबसे मौलिक नियम का प्रावधान करती है।

कि पी. एम. एल. ए. की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध और उससे संबंधित कोई अनुसूचित अपराध उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होगा जिसमें अपराध किया गया है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि धारा 44 (1) (ए) तीन स्थानों पर "अपराध" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है।

लॉन्ड्रिंग। जिस स्थान पर "अनुसूचित अपराध" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, वह विधेय अपराध को दर्शाता है। यह निर्धारित करके कि पी. एम. एल. ए. की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध और उसी से संबंधित अनुसूचित अपराध उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होगा जिसमें "अपराध" किया गया है, धारा 44 (1) (ए) यह स्पष्ट करती है कि यह धारा 43 (1) के तहत गठित विशेष न्यायालय है, जिसे संबंधित अनुसूचित अपराध पर भी मुकदमा चलाने का अधिकार होगा।

एक ही। [पैरा 23] [903-ए-डी] [2023] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धनशोधन के अपराध का संज्ञान लेने के बाद पीएमएलए के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी को न्यायालय में आवेदन जिसने संज्ञान लिया है

अनुसूचित अपराध। इस प्रकार दायर आवेदन पर, जिस न्यायालय ने अनुसूचित अपराध का संज्ञान लिया है, उसे अनुसूचित अपराध से संबंधित मामले को विशेष न्यायालय को सौंपना चाहिए जिसने धन शोधन की शिकायत का संज्ञान लिया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अनुसूचित अपराध का मुकदमा विशेष न्यायालय में होना चाहिए जिसने धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया है। दूसरे शब्दों में, अनुसूचित अपराध का मुकदमा, जहां तक क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का सवाल है, धन के अपराध के मुकदमे का अनुसरण करना चाहिए।

धनशोधन और इसके विपरीत नहीं। [पारस 24,25] [903-ई-एच]

3. चूंकि अधिनियम में अनुसूचित अपराध की सुनवाई और धन शोधन के अपराध की सुनवाई पर विचार किया गया है।

43 (1) , एक संदेह उत्पन्न होने की संभावना है कि क्या सभी अपराधों का एक साथ मुकदमा चलाया जाना है। इस संदेह को दूर करने की कोशिश की जाती है धारा 44 (1) का स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण (i) स्पष्ट करता है कि एक ही न्यायालय द्वारा अपराधों के दोनों समूहों का मुकदमा नहीं होगा -

संयुक्त परीक्षण के रूप में माना जाता है। [पैरा 26] [904-ए-बी]

धनशोधन के अपराध की सुनवाई करने वाला विशेष न्यायालय। [पैरा 27] [904-सी-डी] 5.
इस प्रकार पूरी तस्वीर पी. एम. एल. ए. की धारा 44 और धारा आर. ए. एन. ए. आय. यू. बी. V के प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन के साथ पूरी होती है।

अपने सहायक निदेशक के माध्यम से प्रवर्तन का निर्देश

177 एक बार इस संयुक्त योजना को समझने के बाद, यह स्पष्ट हो जाएगा कि धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (सी) के विशिष्ट अधिदेश को देखते हुए, यह पीएमएलए के तहत गठित विशेष न्यायालय है जिसका अधिकार क्षेत्र होगा।

यहां तक कि निर्धारित अपराध का भी प्रयास करना। यहां तक कि अगर अनुसूचित अपराध का किसी अन्य न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है, तो भी वह न्यायालय संबंधित प्राधिकारी के आवेदन पर,

विशेष न्यायालय जिसने धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया है। [पारस 35 और 36] [908-ई-जी]

6. अपराध की आय से जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं या गतिविधियों में से किसी एक या अधिक में किसी व्यक्ति की भागीदारी,

यह धन शोधन का अपराध है। इन प्रक्रियाओं या गतिविधियों में शामिल हैं, (i) छिपाना; (ii) अधिकार; (iii) अधिग्रहण; (iv) उपयोग; (v) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना; या (vi) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति कर सकता है (i)

अपराध की आय को एक स्थान पर अर्जित करना, (ii) उसे दूसरे स्थान पर अपने कब्जे में रखना, (iii) उसे तीसरे स्थान पर छिपाना, और (iv) चौथे स्थान पर उसी का उपयोग करना। इन स्थानों में से प्रत्येक जिस क्षेत्र में स्थित है, वह वह क्षेत्र होगा जिसमें धन शोधन का अपराध किया गया है। इसे अलग तरह से कहने के लिए, जिस क्षेत्र में अपराध की आय के अधिग्रहण का स्थान स्थित है या इसे कब्जे में रखने का स्थान स्थित है या जिस स्थान पर इसे छुपाया गया है या जिस स्थान पर इसका उपयोग किया गया है, वह वह क्षेत्र होगा जिसमें अपराध किया गया है। [पारस 38,39] [909-ए-सी]

7. इस मामले में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के प्रश्न के लिए उस स्थान के बारे में तथ्य के प्रश्न की जांच की आवश्यकता है जहां अपराध की कथित आय (i) छिपी हुई थी; या (ii) कब्जे में थी; या (iii) अर्जित की गई थी; या (iv) उपयोग की गई थी। तथ्य का यह प्रश्न वास्तव में उन साक्ष्यों पर निर्भर करेगा जो इससे पहले सामने आते हैं

ट्रायल कोर्ट। [पैरा 45] [910-डी]

कौशिक चटर्जी बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य। (2020)

(10) एस. सी. सी. 92-पर निर्भर।

विजय मदनलाल चौधरी और अन्य। वी. भारत संघ और

ओआरएस। 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 929 संदर्भित।

आपराधिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका

(2023 का आपराधिक) No.12।

23] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

सुश्री वृंदा गोवर, सौतिक बनर्जी, आकाश कामरा, सुश्री देविका तुलसीनी, सुश्री मन्नत टिपनिस, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, मुकेश कुमार मरोरिया, जोहेब हुसैन, कानू अग्रवाल, के. परमेश्वर, पद्मेश मिश्रा, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

1. न्यायालय द्वारा जारी समन आदेश को चुनौती देना

विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार-रोधी, सी. बी. आई. अदालत संख्या 1, गाजियाबाद, प्रतिवादी द्वारा धारा 45 के साथ धारा 45 के तहत दर्ज कराई गई शिकायत पर।

44 धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 1 के तहत याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उपरोक्त रिट याचिका दायर की है।

भारत से।

2. हमने याचिकाकर्ता की वकील सुश्री वृंदा गोवर और प्रतिवादी की ओर से भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता को सुना है।

3. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि महामारी के दौरान, उन्होंने एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्राउडफंडिंग अभियान शुरू किया था

"केटो" नाम दिया और अप्रैल 2020 से सितंबर 2021 तक तीन अभियान चलाए। उसी के संबंध में, प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने एक कार्यालय आदेश के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच शुरू की।

दिनांकित 3.8.2021।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद हिंदू आईटी सेल के संस्थापक होने का दावा करने वाले विकास संक्रित्यन ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में 7.9.2021 पर शिकायत दर्ज कराई थी।

आई. पी. सी. की धारा 403, 406, 418 और 420 के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66 डी और काला धन अधिनियम की धारा 4 के तहत कथित अपराध। 5. इस

बीच, याचिकाकर्ता को प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133 (6) के साथ पठित फेमा की धारा 37 के तहत एक आदेश प्राप्त हुआ जिसमें मांग की गई थी

1 संक्षेप में, "पीएमएलए" या "अधिनियम", जैसा भी मामला हो। 2 संक्षेप में, "फेमा"

राणा अयूब बनाम। अपने सहायक निदेशक के माध्यम से प्रवर्तन निदेशक [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

याचिकाकर्ता द्वारा जारी किए गए पिछले कार्यालय आदेश दिनांक 3.8.2021 के जवाब में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अलावा कुछ दस्तावेज

वही मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय।

6. याचिकाकर्ता द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली क्षेत्र-2 कार्यालय को एक विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने ई. सी. आई. आर. नं.

डी. एल. जेड. ओ.-II/58/2021 पर 11.11.2021, गाजियाबाद में विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में। उक्त शिकायत में कहा गया था कि इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन, गाजियाबाद की फाइल पर 7.9.2021 पर दर्ज प्राथमिकी प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत का आधार बनी।

7. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उपरोक्त शिकायत दर्ज करने के बाद, याचिकाकर्ता को दिल्ली जोन-II कार्यालय में तलब किया गया और पीएमएलए की धारा 50 के तहत उसका बयान 15.12.2021 पर दर्ज किया गया।

8. इसके बाद, एच. डी. एफ. सी. बैंक, कोपरखैराने शाखा, नवी मुंबई में याचिकाकर्ता के बैंक खाते को कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश,

महाराष्ट्र, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 4.2.2022 पर पारित किया गया था। अनंतिम कुर्की के आदेश के अनुसार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने 8.3.2022 दिनांकित एक कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया।

9. जबकि चीजें इस तरह से खड़ी थीं, याचिकाकर्ता के खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था, लेकिन इसे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अलग कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका। याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक दूसरी रिट याचिका में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निदेशालय को प्रतिबंधित कर दिया

पी. एम. एल. ए. की धारा 8 के तहत इस आधार पर आगे कदम उठाने से प्रवर्तन कि अनंतिम कुर्की के आदेश की 180 दिनों की वैधता अवधि 4.8.2022 पर वैधानिक रूप से समाप्त हो गई।

10. इसके बाद, विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, भ्रष्टाचार विरोधी,

सीबीआई अदालत संख्या 1, गाजियाबाद ने प्रतिवादी द्वारा दर्ज की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए 29.11.2022 पर एक आदेश पारित किया और याचिकाकर्ता को 13.12.2022 पर पेश होने के लिए बुलाया। उक्त समन आदेश के बारे में पता चलने पर, याचिकाकर्ता उपरोक्त रिट याचिका लेकर आया है। याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के पैराग्राफ 5 (वी) में दावा किया गया है कि "अभी तक कोई समन प्राप्त नहीं हुआ है।" उसके द्वारा और यह कि उसने मामले के विवरण को दर्शाते हुए ई-अदालत की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट संलग्न किया था। हालाँकि, समन आदेश की प्रति का एक प्रिंट आउट रिट याचिका के साथ दाखिल किया जाता है।

23] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. शुरुआत में, याचिकाकर्ता की वकील सुश्री वृन्दा ग्रोवर ने स्पष्ट किया है कि विवादित समन को चुनौती दी गई है।

आदेश केवल क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के प्रश्न तक सीमित है और विवादित समन आदेश को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के अलावा किसी अन्य आधार पर चुनौती नहीं दी जा रही है।

12. संक्षेप में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि पीएमएलए की धारा 44 (1) के तहत एक दंडनीय अपराध है।

अधिनियम की सुनवाई केवल उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें अपराध किया गया है। यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कुछ भी निहित होने के बावजूद है। अधिनियम की धारा 71 उस गैर-बाध्यकारी खंड के अलावा, जिसके साथ धारा 44 (1) शुरू होती है, पी. एम. एल. ए. को भी प्रबल प्रभाव देती है। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि विशेष न्यायालय में

अकेले महाराष्ट्र इस शिकायत का संज्ञान ले सकता था।

13. विजय मदनलाल चौधरी और अन्य मामलों में निर्णय के पैराग्राफ 353 से 358 में इस अदालत की राय पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भारी निर्भरता रखी गई है। बनाम भारत संघ और Ors.4। उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धन शोधन के अपराध का मुकदमा गठित विशेष न्यायालय के समक्ष चलाया जाना चाहिए।

उस क्षेत्र के लिए जिसमें धन शोधन का अपराध किया गया है

और यह कि यदि अनुसूचित अपराध की सुनवाई विशेष न्यायालय द्वारा किसी विशेष अधिनियम के तहत कहीं और की जा सकती है, तो दोनों मुकदमों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन उस क्षेत्र में जहां धन शोधन का अपराध किया गया है। विजय मदनलाल चौधरी (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 356 और 357 इस प्रकार हैं:

" 356. 2013 का संशोधन वास्तव में इस अधिनियम के तहत धन शोधन के अपराध से संबंधित मुकदमों और अनुसूचित अपराध के संबंध में मुकदमे के संबंध में पालन की जाने वाली व्यवस्था को स्पष्ट करता है, जिसमें इस तरह के (अनुसूचित) अपराध की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायालय के समक्ष भी शामिल है। इस खंड के आधार पर, धन शोधन के अपराध से संबंधित मुकदमों को उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय के समक्ष आगे बढ़ने की आवश्यकता है जिसमें धन शोधन का अपराध होता है।

प्रतिबद्ध किया गया है। यदि अनुसूचित अपराध की सुनवाई विशेष न्यायालय द्वारा विशेष अधिनियम के तहत कहीं और की जा सकती है, तो प्रावधान, जैसा कि संशोधित किया गया है, यह स्पष्ट करता है कि इस अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद दोनों मुकदमों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन वह क्षेत्र जहाँ धन शोधन का अपराध किया गया है।

3 संक्षेप में, "Cr.P.C"

42022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 929 राणा अयूब बनाम।

अपने सहायक निदेशक के माध्यम से प्रवर्तन निदेशक [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

357. इसमें, धन शोधन के अपराध को केवल धन का मुकदमा चलाने के लिए नामित विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

धनशोधन अपराध जहाँ धनशोधन का अपराध किया गया है। यह एक विशेष अधिनियम है और बाद में एक कानून होने के नाते, उस समय लागू किसी भी अन्य कानून पर हावी होगा।

2002 के अधिनियम की धारा 71 के संदर्भ में।

14. तथ्यों पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क है कि धन शोधन के कथित अपराध का कोई हिस्सा नहीं था

विशेष न्यायालय, गाजियाबाद के अधिकार क्षेत्र के भीतर और याचिकाकर्ता का बैंक खाता जहाँ अपराध की कथित आय जमा की गई थी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। यहां तक कि बैंक खाते की अस्थायी कुर्की के लिए कार्यवाही थी

नई दिल्ली में शुरू किया गया। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि गाजियाबाद में शिकायत दर्ज करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग था और हिंदू आई. टी. प्रकोष्ठ के संस्थापक के कहने पर ऐसा किया जाना पूरी तरह से दूषित है। यह भी तर्क दिया जाता है कि विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 201 के संदर्भ में प्रत्यर्थी को शिकायत वापस करनी चाहिए थी और यह कि संज्ञान लेने वाले आदेश को भी दिमाग का उपयोग न करने से दूषित किया जाता है।

15. जवाब में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की योजना के तहत, मनी-लॉन्ड्रिंग को अनुसूचित अपराध के संबंध में शिकायत का पालन करना चाहिए। चूंकि अनुसूचित अपराध के संबंध में शिकायत गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में 7.9.2021 पर दर्ज की गई थी, इसलिए प्रतिवादी को अनिवार्य रूप से प्रवर्तन मामले की जानकारी दर्ज करनी थी।

उसी न्यायालय की फाइल पर 11.11.2021 पर रिपोर्ट (ई. सी. आई. आर.), जिसके अधिकार क्षेत्र में अनुसूचित अपराध विचारण योग्य बन गया। इसके अलावा यह

विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता पर एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था और विशेष न्यायाधीश के न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में कई पीड़ित थे जिन्होंने धन का योगदान दिया था। दूसरे शब्दों में, यह विद्वान सॉलिसिटर जनरल का तर्क है कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा वास्तव में विशेष न्यायाधीश, गाजियाबाद के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था।

16. प्रतिद्वंद्वी विवादों से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सामने विचार के लिए दो प्रश्न उठते हैं। वे हैं (i) क्या धन शोधन के अपराध का मुकदमा अनुसूचित/विधेय [2023] 3 एस. सी. आर. के मुकदमे का अनुसरण करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपराध या इसके विपरीत; और (ii) क्या विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार-रोधी, सी. बी. आई. न्यायालय संख्या 1, गाजियाबाद के न्यायालय के बारे में कहा जा सकता है कि उसने अतिरिक्त-क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रयोग किया था, भले ही कथित अपराध उक्त न्यायालय की अधिकारिता के भीतर नहीं किया गया था।

17. प्रश्न संख्या 1 का उत्तर खोजने के लिए, यह आवश्यक है

हम पी. एम. एल. ए. के कुछ प्रावधानों पर ध्यान दें। 18. "मनी लॉन्ड्रिंग" शब्द को अधिनियम की धारा 2 (1) (पी) में उसी अर्थ के लिए परिभाषित किया गया है जो धारा 3 में दिया गया है।

अधिनियम की धारा 3 किसी व्यक्ति को धन के अपराध का दोषी ठहराती है।

धनशोधन, यदि वह (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करता है; या (ii) जानबूझकर सहायता करता है या (iii) जानबूझकर एक पक्ष है; या (iv) वास्तव में किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है। ऐसी प्रक्रिया या गतिविधि को जोड़ा जाना चाहिए।

"अपराध की आय" के लिए, जिसमें इसे छिपाना या कब्जा करना या अधिग्रहण या उपयोग शामिल है। इसके अलावा, अपराध की आय से जुड़ी ऐसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल व्यक्ति को इस रूप में पेश या दावा करना चाहिए

वेदाग संपत्ति। धारा 3 के तहत स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि

भले ही संलिप्तता निम्नलिखित गतिविधियों या प्रक्रियाओं में से एक या अधिक में हो, अर्थात्, (i) छिपाना; (ii) कब्जा; (iii) अधिग्रहण; (iv) उपयोग; (v) इसे वेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना; या (vi) इसे वेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना, धन शोधन का अपराध माना जाएगा।

19. इस प्रकार, धारा 3 में दो आवश्यक अंग शामिल हैं, अर्थात् (i) किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में भागीदारी; और (ii) ऐसी प्रक्रिया का संबंध।

या अपराध की आय के लिए गतिविधि। "अपराध की आय" पद को धारा 2 (1) (यू) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है किसी अनुसूचित अपराध या ऐसी संपत्ति के मूल्य से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई कोई संपत्ति या जहां ऐसी संपत्ति है। संपत्ति को देश के बाहर ले जाया या रखा जाता है, फिर देश के भीतर या विदेश में रखे गए मूल्य के बराबर संपत्ति।

20. पी. एम. एल. ए. दोतरफा दृष्टिकोण प्रदान करता है, एक अपराध की आय से निपटने के लिए और दूसरा व्यक्ति से निपटने के लिए।

धन शोधन के अपराध का दोषी। जबकि अध्याय III और अध्याय VI अपराध की आय से निपटने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, कुर्की की प्रक्रिया के माध्यम से, निर्णय के माध्यम से पुष्टि और

विशेष न्यायाधिकरण के लिए अपीलीय उपचार, अध्याय VII विशेष न्यायालयों द्वारा धन शोधन करने वालों के अभियोजन से संबंधित है।

21. अधिनियम की धारा 43 (1) में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान है।

उच्च न्यायालय से। धारा 43 की उप-धारा (2) विशेष आर. ए. एन. ए. आय. यू. बी. V. को सशक्त बनाती है।

अपने सहायक निदेशक के माध्यम से प्रवर्तन निदेशक [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

धारा 43 (1) के तहत गठित न्यायालय, पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध का मुकदमा चलाने के लिए भी है, जिसके साथ आरोपी पर उसी मुकदमे में Cr.P.C के तहत आरोप लगाया जा सकता है। अर्थात्, धारा 43 (1) के तहत एक विशेष न्यायालय का गठन मुख्य रूप से धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से किया जाता है। लेकिन धारा 43 की उप-धारा (2) इस तरह के एक पर एक अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है

विशेष न्यायालय किसी अन्य अपराध की सुनवाई करेगा जिसके लिए अभियुक्त पर उसी मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है। धारा 43 इस प्रकार है:

" 43. विशेष न्यायालय। (1) केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के मुकदमे के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करेगी।

क्षेत्र या क्षेत्र या ऐसे मामले या वर्ग या मामलों के समूह के लिए जो हो सकता है

अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा में, "उच्च न्यायालय" का अर्थ है उस राज्य का उच्च न्यायालय जिसमें एक सत्र न्यायालय नामित किया गया है -

इस तरह के पदनाम से ठीक पहले विशेष न्यायालय काम कर रहा था।

(2) इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की सुनवाई करते समय, एक विशेष न्यायालय उप-अधिनियम में निर्दिष्ट अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध की भी सुनवाई करेगा। धारा (1), जिसके साथ अभियुक्त पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत उसी समय आरोप लगाया जा सकता है।

मुकदमा "।

22.

धारा 44 क्षेत्रीय अधिकारिता के प्रश्न से संबंधित है

धारा 43 (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय। प्रारम्भ में, धारा 44 (1) दो अलग-अलग आकस्मिकताओं पर ध्यान देती है, अर्थात् (i) ऐसे मामले जहां अनुसूचित अपराध के साथ-साथ धन शोधन का अपराध भी शामिल है।

उसी विशेष न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रतिबद्ध

धारा 43 (1) के तहत गठित; और (ii) ऐसे मामले जहां न्यायालय ने अनुसूचित अपराध का संज्ञान लिया है, विशेष न्यायालय के अलावा अन्य है जिसने धन शोधन के अपराध की शिकायत का संज्ञान लिया है। धारा 44 (1) इस प्रकार है:

" 44. विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराध।

(1) दंड संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद

प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2), -

(क) धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध और उस धारा के तहत अपराध से जुड़ा कोई अनुसूचित अपराध उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होगा जिसमें अपराध किया गया था।

किया गया है:

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ग) यदि वह न्यायालय जिसने अनुसूचित अपराध का संज्ञान लिया है, विशेष न्यायालय के अलावा अन्य है जिसने उप-अधिनियम के तहत धन शोधन के अपराध की शिकायत का संज्ञान लिया है। खंड (ख), वह इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा एक आवेदन पर, अनुसूचित अपराध से संबंधित मामले को विशेष न्यायालय को सौंपेगा और विशेष न्यायालय, ऐसा मामला प्राप्त होने पर, उस स्तर से उससे निपटने के लिए आगे बढ़ेगा जिस पर वह किया गया है।

(घ) एक विशेष न्यायालय अनुसूचित अपराध या धन शोधन के अपराध की सुनवाई करते समय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाएगा, जैसा कि यह सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे पर लागू होता है।

स्पष्टीकरण। शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि,

अनुसूचित अपराध का, और एक ही न्यायालय द्वारा अपराधों के दोनों समूहों के मुकदमे को संयुक्त मुकदमे के रूप में नहीं माना जाएगा; ((ii) शिकायत में आगे की जांच के संबंध में कोई भी बाद की शिकायत शामिल मानी जाएगी जो अपराध के संबंध में शामिल किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई और सबूत, मौखिक या दस्तावेजी लाने के लिए की जा सकती है, जिसके लिए शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है, चाहे मूल शिकायत में इसका नाम हो या नहीं। राणा अयूब बनाम।

अपने सहायक निदेशक के माध्यम से प्रवर्तन निदेशक [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

पी. एम. एल. ए. की धारा 4 के तहत दंडनीय और उससे जुड़े किसी भी अनुसूचित अपराध की सुनवाई उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें अपराध किया गया है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि धारा 44 (1) (ए) केवल "अनुसूचित अपराध" अभिव्यक्ति के विपरीत तीन स्थानों पर "अपराध" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है। एक बार इस उपयोग का कोई महत्व नहीं है। उन तीनों स्थानों पर जहां अकेले "अपराध" शब्द का उपयोग किया जाता है, यह धन शोधन के अपराध को दर्शाता है। जिस स्थान पर "अनुसूचित अपराध" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, वह विधेय अपराध को दर्शाता है। यह निर्धारित करके कि पी. एम. एल. ए. की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध और उससे जुड़े किसी भी अनुसूचित अपराध की सुनवाई उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें "अपराध" किया गया है, धारा 44 (1) (ए) यह स्पष्ट करती है कि यह धारा के तहत गठित विशेष न्यायालय है।

43 (1) , जो उसी से जुड़े अनुसूचित अपराध पर भी मुकदमा चलाने के लिए सशक्त होगा।

24. इस तरह के एक सामान्य लेकिन मौलिक नियम का मानचित्रण/निर्धारण करने के बाद, अधिनियम अधिक जटिल स्थिति से निपटने के लिए आगे बढ़ता है।

धारा 44 (1) (ग)। यह सवाल कि क्या होता है यदि न्यायालय जिसने अनुसूचित अपराध का संज्ञान लिया है, विशेष न्यायालय के अलावा अन्य है जिसने धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया है।

इसका उत्तर धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा दिया जाना अपेक्षित है। यदि अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने वाला न्यायालय विशेष न्यायालय से अलग है जिसने धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया है, तो पीएमएलए के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत प्राधिकरण को उस न्यायालय में आवेदन करना चाहिए जिसने अनुसूचित अपराध का संज्ञान लिया है। इस प्रकार दायर आवेदन पर, जिस न्यायालय ने अनुसूचित अपराध का संज्ञान लिया है, उसे अनुसूचित अपराध से संबंधित मामले को विशेष न्यायालय को सौंपना चाहिए जिसने धन शोधन की शिकायत का संज्ञान लिया है।

25. इसलिए, यह स्पष्ट है कि अनुसूचित अपराध का मुकदमा विशेष न्यायालय में होना चाहिए जिसने इसका संज्ञान लिया है।

धन शोधन का अपराध। दूसरे शब्दों में, अनुसूचित अपराध का मुकदमा, जहां तक क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का सवाल है,

मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के मुकदमे का पालन करना चाहिए न कि गलत तरीके से

इसके विपरीत।

23] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. चूँकि अधिनियम अनुसूचित अपराध की सुनवाई और धनशोधन के अपराध की सुनवाई केवल धारा 43 (1) के तहत गठित विशेष न्यायालय के समक्ष करने पर विचार करता है, इसलिए इस बात पर संदेह उत्पन्न होने की संभावना है कि क्या सभी अपराधों की सुनवाई एक साथ की जानी है। यह संदेह है कि धारा 44 (1) के स्पष्टीकरण (i) द्वारा हटाने की मांग की गई। स्पष्टीकरण (i) स्पष्ट करता है कि एक ही न्यायालय द्वारा अपराधों के दोनों समूहों का विचारण

इसे संयुक्त परीक्षण के रूप में नहीं माना जाएगा।

27. धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (सी) के सावधानीपूर्वक विच्छेदन से पता चलता है कि वे विशेष न्यायालय को प्रधानता प्रदान करते हैं।

पीएमएलए की धारा 43 (1) के तहत गठित। इन दो खंडों में दो नियम हैं, अर्थात्: (i) पी. एम. एल. ए. के तहत दंडनीय अपराध के साथ-साथ उससे जुड़े अनुसूचित अपराध का उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा जिसमें धन शोधन का अपराध किया गया है; और (ii) यदि किसी एक न्यायालय द्वारा अनुसूचित अपराध के संबंध में संज्ञान लिया गया है और विशेष न्यायालय द्वारा धन शोधन के अपराध के संबंध में संज्ञान लिया गया है, तो अनुसूचित अपराध की सुनवाई करने वाला न्यायालय इसे धन शोधन के अपराध की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायालय को सौंपेगा। 28. यह केवल इसलिए है क्योंकि धारा 43 (1) के तहत गठित विशेष न्यायालय को प्रधानता प्रदान की गई है कि धारा 44 (1) "दंड संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद" शब्दों से शुरू होती है।

प्रक्रिया "। यद्यपि पी. एम. एल. ए. में धारा 44 (1) और धारा 45 (1) दोनों में Cr.P.C के संबंध में एक गैर-अडचन खंड शामिल है, लेकिन दो अन्य प्रावधान हैं जहां दंड प्रक्रिया संहिता है -

विशेष रूप से एक विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होने के लिए घोषित किया गया। धारा 46 (1) विशेष रूप से विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिए Cr.P.C के प्रावधानों को लागू करती है। इसी तरह, पी. एम. एल. ए. की धारा 65 आई. डी. 1 के प्रावधानों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती, कुर्की, जब्ती, जांच, अभियोजन और अधिनियम के तहत अन्य सभी कार्यवाही पर लागू करती है।

29. इसलिए, यह स्पष्ट है कि विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही सहित अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही पर Cr.P.C के प्रावधान लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उन्हें विशेष रूप से बाहर रखा गया है। इसलिए, पी. एम. एल. ए. की धारा 71 को धारा 46 (1) और धारा 65 के अनुरूप माना जाना चाहिए।

30. विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर असर डालने वाले पी. एम. एल. ए. के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद, आइए हम राणा अयूब बनाम.

अपने सहायक निदेशक के माध्यम से प्रवर्तन निदेशक [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

अब हमारा ध्यान Cr.P.C के कुछ प्रावधानों की ओर दें, जो क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के सवाल से संबंधित हैं।

31. जैसा कि इस न्यायालय ने कौशिक चटर्जी बनाम हरियाणा राज्य और Ors.³ में इंगित किया है, आपराधिक मामले में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का सवाल।

मामले इस बात के इर्द-गिर्द घूमते हैं, (i) अपराध करने का स्थान; या (ii) वह स्थान जहाँ किसी कार्य का परिणाम होता है, जो दोनों अपराध हैं; या (iii) वह स्थान जहाँ अभियुक्त पाया गया था; या (iv) वह स्थान जहाँ पीड़ित पाया गया था; या (v) वह स्थान जहाँ संपत्ति पाई गई थी।

जिसके संबंध में अपराध किया गया था, पाया गया था; या (vi) वह स्थान जहाँ अपराध की विषय वस्तु बनाने वाली संपत्ति को, जैसा भी मामला हो, वापस करने या उसका हिसाब आदि करने की आवश्यकता थी।

32. जैसा कि कौशिक चटर्जी (ऊपर) में व्यक्त किया गया है, दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र क्षेत्रीय और आर्थिक सीमाओं द्वारा सीमित है, लेकिन आपराधिक अदालत का अधिकार क्षेत्र (i) अपराध और/या (ii) अपराधी द्वारा निर्धारित किया जाता है।

33. Cr.P.C के प्रावधानों के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर चर्चा को कौशिक चटर्जी में निर्णय के पैराग्राफ 19 से 21 में दिए गए सिद्धांतों को निकालकर कम किया जा सकता है। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

" 19. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XIII में पूछताछ और परीक्षणों में आपराधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रावधान हैं। संहिता (i) जांच; (ii) के बीच अंतर रखती है।

जांच; और (iii) मुकदमा। "जांच" और "जांच" शब्दों को धारा 2 के खंड (जी) और (एच) में क्रमशः परिभाषित किया गया है।

20. जांच और परीक्षणों में आपराधिक न्यायालयों की अधिकारिता के संबंध में संहिता की धारा 177 से 184 (अध्याय XIII में निहित) में निर्धारित सिद्धांतों को सरल शब्दों में संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

20.1 . प्रत्येक अपराध की जांच और मुकदमा आम तौर पर उस अदालत द्वारा किया जाना चाहिए जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में यह किया गया था। यह नियम धारा 177 में पाया जाता है। धारा 177 में पाई जाने वाली "स्थानीय अधिकारिता" अभिव्यक्ति को धारा 2 (जे) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में, जिसका अर्थ है वह स्थानीय क्षेत्र जिसके भीतर -

5 2020 (10) एससीसी 92 [2023] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय या मजिस्ट्रेट संहिता के तहत अपनी सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।
20.2 . उस स्थान के बारे में अनिश्चितता के मामले में जिसमें,

कई स्थानीय क्षेत्रों में, एक अपराध किया गया था, ऐसे किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला न्यायालय ऐसे अपराध की जांच या मुकदमा चला सकता है।

20.3 . जहाँ कोई अपराध आंशिक रूप से एक क्षेत्र में किया जाता है और आंशिक रूप से

दूसरे में, ऐसी किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा इसकी जांच या मुकदमा चलाया जा सकता है।

20.4 . निरंतर अपराध के मामले में जो किया जाता है

एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में, ऐसी किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय द्वारा इसकी जांच या मुकदमा चलाया जा सकता है।

20.5 . जहाँ किसी अपराध में विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल हैं, वहाँ ऐसी किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालत द्वारा इसकी जांच या मुकदमा चलाया जा सकता है। (संख्या 2 से 5 का पता धारा 178 से लगाया जा सकता है)

अभिरक्षा आदि से भागने पर अपराध की जांच की जा सकती है और उस अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में या तो अपराध किया गया था या आरोपी व्यक्ति पाया गया था।

20.9 . अपहरण या अपहरण के अपराध के मामले में, यह

जिस अदालत के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यक्ति का अपहरण किया गया था या उसे पहुँचाया गया था या छिपाया गया था या हिरासत में लिया गया था, उससे पूछताछ या मुकदमा चलाया जाएगा।

20.10 . चोरी, जबरन वसूली या डकैती के अपराधों की जांच की जा सकती है। ऐसी अदालत में या उसके द्वारा मुकदमा चलाया जाता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया था या चोरी की गई संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया था, प्राप्त किया गया था या उसे बनाए रखा गया था।

राणा अयूब बनाम। प्रवर्तन का निर्देश

रौघ इसके सहायक निदेशक हैं [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

20.11 . अपराधिक गबन या अपराधिक विश्वासघात के अपराध की जांच या मुकदमा उस अदालत द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया था या संपत्ति का कोई हिस्सा प्राप्त किया गया था या रखा गया था या आरोपी व्यक्ति द्वारा उसे वापस करने या हिसाब देने की आवश्यकता थी।

स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया था या चोरी की गई संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास थी, जिसे पता था कि यह चोरी की संपत्ति है। (नं. 8 से 12 धारा 181 में पाए जाते हैं) 20.13 . एक अपराध जिसमें धोखाधड़ी शामिल है, यदि पत्रों या दूरसंचार संदेशों के माध्यम से किया जाता है, तो किसी भी अदालत द्वारा जांच या मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए थे या प्राप्त किए गए थे।

20.14 . धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के अपराध की जांच या मुकदमा उस अदालत द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में संपत्ति उस व्यक्ति द्वारा दी गई थी जिसे धोखा दिया गया था या आरोपी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया था। 20.15 . विवाह से संबंधित कुछ

अपराध जैसे कि आई. पी. सी. की धारा 494 (पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान फिर से विवाह करना) और आई. पी. सी. की धारा 495 (पूर्व विवाह को छिपाकर धारा 494 के तहत अपराध करना) की जांच या मुकदमा उस अदालत द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया था या अपराधी पिछली बार पहली शादी से जीवनसाथी के साथ रहा था। (नं. 13 से 15 धारा 182 में पाए जाते हैं)

20.16 . यात्रा या यात्रा के दौरान किया गया अपराध

किसी ऐसे न्यायालय के माध्यम से या जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में वह व्यक्ति या वस्तु उस यात्रा या यात्रा के दौरान पारित हुई हो, उससे पूछताछ या मुकदमा चलाया जा सकता है। (धारा 183)।

20.17 . धारा 219 के तहत आने वाले मामले (बारह महीने के अंतराल के भीतर किए गए एक ही तरह के तीन अपराध) एक ही व्यक्ति के संबंध में या नहीं), धारा के तहत आने वाले मामले

220 (एक से अधिक अपराधों के करने, एक ही लेन-देन के रूप में एक साथ किए गए कार्यों की एक श्रृंखला में) और धारा 221 के तहत आने वाले मामलों (जहां यह संदेह है कि क्या अपराध किए गए हैं) की जांच या मुकदमा किसी भी अदालत द्वारा किया जा सकता है।

किसी भी अपराध की जांच करने या मुकदमा चलाने में सक्षम। (धारा 184)।

23] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. धारा 177 से 184 के अलावा, जो विस्तृत रूप से निर्धारित की गई है, अधिकारिता से संबंधित नियमों, संहिता के अध्याय XIII में कुछ अन्य धाराएं भी शामिल हैं। धारा 185 अधिकार प्रदान करती है राज्य सरकार किसी भी जिले में मुकदमे के लिए किए गए किसी भी मामले या मामलों के वर्ग को किसी भी सत्र प्रभाग में मुकदमा चलाने का आदेश देगी। धारा 186 उच्च न्यायालय को उस मामले में अधिकार देती है, जहां दो या दो से अधिक न्यायालयों ने एक ही अपराध का संज्ञान लिया है और यह सवाल उत्पन्न हुआ है कि उनमें से किसे अपराध की जांच करनी चाहिए या मुकदमा चलाना चाहिए, उस जिले को तय करने के लिए जहां जांच या मुकदमा होगा। धारा 187 मजिस्ट्रेट की शक्तियों की बात करती है, ऐसे मामले में जहां

अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यक्ति ने एक अपराध किया है

उसकी अधिकारिता के बाहर, लेकिन ऐसी अधिकारिता के भीतर इसकी जांच या मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। धारा 188 और 189 के बारे में

भारत के बाहर किए गए अपराध।

34. यह Cr.P.C की धारा 177 से 184 तक निकाले गए सिद्धांतों से देखा जा सकता है कि लगभग सभी आकस्मिकताएँ जो संभावित हैं

इन प्रावधानों में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और उन्हें निर्धारित किया गया है।

35. एकमात्र आकस्मिकता जो Cr.P.C के उपरोक्त प्रावधानों में प्रदान नहीं की जा सकती थी, शायद वह है जहां धन का अपराध होता है।

धनशोधन किया जाता है। यही कारण है कि धारा 44 (1) एक अबाधित खंड के साथ शुरू होती है। इस प्रकार पूरी तस्वीर पीएमएलए की धारा 44 और Cr.P.C की धारा 177 से 184 के प्रावधानों के संयुक्त पठन के साथ पूरी होती है।

36. एक बार इस संयुक्त योजना को समझने के बाद, यह स्पष्ट हो जाएगा कि धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (सी) के विशिष्ट अधिदेश को देखते हुए, यह पीएमएलए के तहत गठित विशेष न्यायालय है कि

अनुसूचित अपराध पर भी मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र होगा। यहां तक कि अगर अनुसूचित अपराध का किसी अन्य न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है, तो भी वह न्यायालय संबंधित प्राधिकारी के आवेदन पर, विशेष न्यायालय को ऐसा ही करेगा, जिसने धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया है। यह हमारे सामने रखे गए पहले प्रश्न का उत्तर देता है।

37. हमारे विचार के लिए उत्पन्न होने वाले दूसरे प्रश्न पर आते हुए, धारा 44 की उप-धारा (1) का खंड (ए) इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि धन शोधन का अपराध केवल विशेष न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है।

जिस क्षेत्र में धन शोधन का अपराध किया गया है, उसके लिए न्यायालय का गठन किया गया है। यह पता लगाने के लिए कि किस क्षेत्र में धन शोधन का अपराध किया गया है, हमें पीएमएलए की धारा 3 की परिभाषा पर वापस जाना पड़ सकता है।

राणा अयूब बनाम। अपने सहायक निदेशक के माध्यम से प्रवर्तन निदेशक [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

38. जैसा कि हमने पहले बताया है, किसी भी एक या अधिक कुछ प्रक्रियाओं या गतिविधियों में किसी व्यक्ति की भागीदारी

अपराध की आय, धन शोधन का अपराध है। इन प्रक्रियाओं या गतिविधियों में शामिल हैं, (i) छिपाना; (ii) कब्जा; (iii) अधिग्रहण; (iv) उपयोग; (v) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना; या (vi) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना।

39. दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति (i) अपराध की आय को एक स्थान पर अर्जित कर सकता है, (ii) उसे दूसरे स्थान पर अपने कब्जे में रख सकता है, (iii)

उसी को तीसरे स्थान पर छिपाएँ, और (iv) चौथे स्थान पर उसी का उपयोग करें। इन स्थानों में से प्रत्येक जिस क्षेत्र में स्थित है, वह वह क्षेत्र होगा जिसमें धन शोधन का अपराध किया गया है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, वह क्षेत्र जिसमें अपराध की आय के अधिग्रहण का स्थान स्थित है या इसे कब्जे में रखने का स्थान स्थित है या जिस स्थान पर इसे छिपाया गया है वह स्थान स्थित है या वह स्थान है जिसमें यह है।

उपयोग किया गया स्थान, वह क्षेत्र होगा जिसमें अपराध किया गया है। 40. इसके अलावा, "अपराध की आय" शब्दों की परिभाषा आपराधिक अपराध के परिणामस्वरूप "संपत्ति प्राप्त करने या प्राप्त करने" पर केंद्रित है।

अनुसूचित अपराध से संबंधित गतिविधि। इसलिए, वह क्षेत्र जिसमें संपत्ति प्राप्त की जाती है या प्राप्त की जाती है या यहां तक कि रखी जाती है या छुपाई जाती है, वह होगा

वह क्षेत्र जिसमें धन शोधन का अपराध किया जाता है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपराध की आय के रूप में जो संलग्न किया गया था, वह नवी मुंबई, महाराष्ट्र में याचिकाकर्ता का बैंक खाता था और इसलिए प्रतिवादी के अनुसार भी धन शोधन का अपराध महाराष्ट्र में किया गया है। 42. लेकिन उक्त विवाद की धारा 3 के तहत स्पष्टीकरण (i) में उल्लिखित छह अलग-अलग प्रकार की प्रक्रियाओं या गतिविधियों की अनदेखी करता है।

अधिनियम, जैसा कि अपराध की आय से संबंधित है, अर्थात्, छिपाना, कब्जा, अधिग्रहण या उपयोग, आदि।

43. याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म पर अप्रैल 2020 से सितंबर 2021 तक तीन अभियान चलाए।

"केटो" नाम दिया गया। अभिलेख पर दी गई दलीलों से, हम (i) धन प्रदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या; और (ii) उन स्थानों का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं जहां दानदाता स्थित थे।

23] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44. एच. डी. एफ. सी. बैंक में याचिकाकर्ता का बैंक खाता,

गतिविधि अर्थात् अपराध की आय का अधिग्रहण (यदि वे वास्तव में हैं) देश/दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोगों द्वारा ऑनलाइन धन हस्तांतरण के साथ आभासी मोड में किया गया है। यदि अधिग्रहण वास्तविक भौतिक दुनिया में हुआ है, तो अधिकार क्षेत्र के सवाल के संबंध में कठिनाई कम होती। चूंकि अधिग्रहण आभासी दुनिया में हुआ है, इसलिए जिन स्थानों से धन का ऑनलाइन हस्तांतरण हुआ, वे केवल याचिकाकर्ता या शायद उनके बैंकों को ही पता हैं। 45. इसलिए, इस मामले में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के प्रश्न के लिए उस स्थान के बारे में तथ्य के प्रश्न की जांच की आवश्यकता है जहां

अपराध की कथित आय (i) छिपाई गई थी; या (ii) कब्जे में थी; या (iii) अर्जित की गई थी; या (iv) उपयोग की गई थी। तथ्य का यह प्रश्न वास्तव में उस साक्ष्य पर निर्भर करेगा जो विचारण न्यायालय के समक्ष सामने आता है। इस संबंध में कौशिक चटर्जी के निर्णय के पैराग्राफ 38 को निकालना उपयोगी होगा जो इस प्रकार है: -

" 38. लेकिन जो भी हो, उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है:
38.1 . कि किसी "अपराध" या "अपराधी" पर मुकदमा चलाने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा और साथ ही क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का मुद्दा, निर्भर करता है

साक्ष्य के माध्यम से स्थापित तथ्यों पर।
38.2 . कि यदि मुद्दा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का है, तो इसका निर्णय विभिन्न नियमों के संबंध में किया जाना चाहिए।

संहिता की धारा 177 से 184 तक।

38.3 . कि इन प्रश्नों को अपराध की सुनवाई करने वाली अदालत के समक्ष उठाना पड़ सकता है और ऐसी अदालत उसी पर विचार करने के लिए बाध्य है।

46. इसलिए, हमारा विचार है कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को एक रिट याचिका में तय नहीं किया जा सकता है, खासकर जब अपराध के स्थान/स्थानों के बारे में गंभीर तथ्यात्मक विवाद हो। इसलिए, यह प्रश्न याचिकाकर्ता द्वारा विशेष न्यायालय के समक्ष उठाया जाना चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर उन स्थानों के साक्ष्य पर निर्भर करेगा जहां धारा 3 में उल्लिखित कोई एक या अधिक प्रक्रियाएं या गतिविधियाँ की गई थीं। इसलिए, राणा अयूब V देते हुए।

अपने सहायक निदेशक के माध्यम से प्रवर्तन

निदेशक [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के समक्ष क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता, इस रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है। कोई आदेश नहीं होगा

लागतों के लिए।

अंकित ज्ञान (हर्षद सुंदर और महेंद्र यादव, एलसीआरएस द्वारा सहायता प्राप्त)